श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल,
राजस्थान का उद्‌बोधन

भारतीय उद्योग परिसंघ का दूसरा संस्करण सम्मेलन

दिनांक 10 नवम्बर, 2020 **समय प्रात : 11.30 बजे**

स्थान : राजभवन, जयपुर

अनुसंधान विकास एवं नवचारों के जरिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के इस सम्मेलन में आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे याद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

आज के इस सम्मेलन में यहां उपस्थिति–

- श्री विशाल बैद, अध्यक्ष, सीआईआई राजस्थान राज्य परिषद।
- डॉ. आर सोंडे, बोर्ड सदस्य, थर्मैक्स लिमिटेड।
- श्री मयंक सिंघल, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पीआई इंडस्ट्रीज।
- श्री वेंकटेश्वर राव यदलापल्ली, ग्लोबल आरएंडडी हेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड।
- श्री ऋषि बैद, संयुक्त प्रबंध निदेशक, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड।
- श्री संजय साबू, उपाध्यक्ष, सीआईआई राजस्थान राज्य परिषद।
- श्री नितिन गुप्ता, निदेशक और राज्य प्रमुख, सीआईआई राजस्थान।
- औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधिगण, सीआईआई के प्रतिष्ठित सदस्यगण और मीडिया के प्रतिनिधिगण।

किसी भी देश के औद्योगिक विकास और वहां की आर्थिक सम्पन्नता का सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए यह जरूरी है कि औद्योगिक विकास में समयानुरूप तकनीक को अपनाने के साथ ही अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के नवाचारों को अपनाया जाए। विश्व के विकसित देशों जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि ने यही किया है। वहां की औद्योगिकी इकाईयों ने विज्ञान और प्रोद्योगिकी के साथ ही उद्योगों के विकास में नवाचारों को अपनाते हुए उच्च विकासयुक्त वृद्धि की रणनीति पर कार्य किया है।

भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच के साथ अधुनातन प्रौद्योगिकी और नवाचारों को अपनाते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संशाधनों का समुचित सदुपयोग करते हुए भविष्य के आर्थिक विकास की रणनीति पर कार्य कर रहा है।

देश में इस समय शोध एवं विकास आधारित अर्थव्यवस्था में उद्योगों के लिए नवीन अवसर उपलब्ध हुए हैं। नीति आयोग द्वारा सभी मंत्रालयों को अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत शोध और अनुसंधान पर व्यय करने के लिए रखे जाने का इसीलिए कहा गया है कि समय के साथ उद्योग–धन्धों को नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों का लाभ मिल सके।

यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि सितम्बर 2020 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में विश्व के 50 प्रमुख देशों में शुमार हुआ है। ऐसा अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसका अर्थ है कि आधुनिक भारत विज्ञान और प्रोद्योगिकी के एक मजबूत ढांचे की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

इस समय भारत सूचना एवं संचार तकनीक, सेवा क्षेत्र के निर्यात, विज्ञान एवं इंजिनियरिंग में उपलब्ध स्नातकों, ऑनलाईन सरकारी सेवाओं और शोध एवं अनुसंधान पहल विश्व कंपनियों में शीर्ष 15 के सूचकांक पर है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास में हमारे पास संभावनाओं का बड़ा आकाश मौजूद है।

जरूरत इस बात की है कि विभिन्न क्षेत्रों की हमारी विशेषज्ञता और विशिष्टता की उपलब्धता को पहचानते हुए औद्योगिक विकास के लिए बेहतर वातावरण बनाया जाए।

वैश्वीकरण के इस दौर में यह भी जरूरी है कि सभी उद्योग अपने स्तर पर अनुसंधान और डिजाइन (Design Capability) के नवाचारों को प्रोत्साहित व संचालित करने वाली एक संस्थागत प्रणाली अपने यहां विकसित करे। इसके बगैर औद्योगिक क्षेत्र में देश एक महत्त्वपूर्ण विनिर्माण शक्ति नहीं बन सकता।

मुझे भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं उद्योग मंत्रालय में भी कार्य करने का अवसर मिला है। यह बताना चाहता हूं कि तब बतौर मंत्री भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, में हमने देशभर के राज्यों में पेटेंट सूचना केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र जैसी पहल की थी।

मेरा भारतीय उद्योग परिसंघ से आग्रह है कि वे राज्यों में नवीनतम अनुसंधान और डिजायन से संबंधित पेटेंट कराने के लिए उद्यमियों को आगे लाए।

यह देखने में आया है कि हमारे यहां शोध और अनुसंधान के साथ नवीनतम डिजायन विकसित तो होते हैं परन्तु उनका पेटेंट नहीं हो पाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में पेटेंट के महत्व को देखते हुए इस संबंध में पहल की जानी चाहिए।

यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्थानीय स्तर पर उद्यमियों द्वारा जो नवाचार होते हैं, उन्हें कई बार मंच नहीं मिल पाता है। बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद, डिजायन और शोध से जुड़ी चीजों को इसीलिए वृहद स्तर पर पहचान नहीं मिल पाती है। स्थानीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर ही काम करते हैं। जरूरत इस बात की भी है कि ऐसे स्थानों पर लोकल नवाचार, डिजायन के नवीनतम रूपों और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों की पहचान कर भारतीय उद्योग परिसंघ उन्हें अपने स्तर पर आगे लाने का प्रयास करें।

भारतीय उद्योग परिसंघ से मेरा यह भी अनुरोध है कि एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में वह सहयोग करे जिससे उद्यम के स्तर पर मानवीय व तकनीकी क्षमता का विकास करने के साथ ही नवाचारों के निरन्तर प्रोत्साहन का कार्य हो सके।

अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में देश में क्षमतातों की कमी नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार प्रणाली के लिये आवश्यक मुख्य्‍ घटकों का विकास औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा यदि अपने स्तर पर किया जाता है तो इसका लाभ सभी स्तरों पर मिल सकता है।

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाजार, क्षमता, कुशल श्रम की उपलब्धता और अनुसंधान एवं विकास की आज भी हमारे देश में अन्य देशों के मुकबाले बहुत कम लागत है।

इस अवसर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक दक्षता को केन्द्र में रखते हुए क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

हाल ही में राजस्थान में नई शिक्षा नीति को व्यवहार में विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए मैंने इस बात पर ही अधिक जोर दिया है कि विश्वविद्यालय अपने यहां ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनसे विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के समय ही उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित हो सके।

नई शिक्षा नीति में शोध, अनुसंधान एवं नवाचारों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से मेरा यह मानना है कि देश में शैक्षणिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी को समझने और उसको निर्मित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

देश में नवाचार और उद्यमशीलता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना के साथ ही प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रयोग हेतु देशभर में अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज की स्थापना के जो निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किए गए हैं, उसके मूल में यही है कि देश तेजी से औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो। इसी संबंध में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (BIRAC) द्वारा बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट (बी.आई.जी.) की शुरुआत की गई है। युवा स्टार्टअप को अनुदान प्रदान करने की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण है।

औद्योगिक विकास के लिए शोध, अनुसंधान और नवाचार जितने जरूरी है, उतनी अधिक जरूरत **शिक्षित अर्थव्यवस्था** की है। शिक्षित अर्थव्यवस्था का मेरा आशय यह है कि औद्योगिक विकास के लिए सभी की साझा समझ सभी स्तरों पर विकसित हो।

उच्च शिक्षा में औद्योगिक विकास की समझ विकसित करने के पाठ्यक्रम जुड़ते हैं, अध्ययन के साथ ही व्यावसायिक कौशल पर जोर दिया जाता है तो आधुनिक शोध, अनुसंधान और नवाचारों की ज्ञान अर्थव्यवस्था का निर्माण तेजी से किया जा सकता है।

ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का अर्थ ही है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आधुनिक अनुसंधान एवं नवाचारों से सतत विकास को संभव बनाना।

मैं यह मानता हूं कि विश्वविद्यालय ज्ञान और नवाचार की पौधशालाएं हैं। औद्योगिक समूह सामाजिक दायित्व निर्वहन के अंतर्गत अपने लाभ के हिस्से का कुछ प्रतिशत यदि शिक्षा में व्यय करते हैं तो इसका दीर्घकालीन लाभ औद्योगिक विकास को मिल सकता है।

यह सम्मेलन अनुसंधान और नवाचारों के जरिए तेजी से औद्योगिक विकास को केन्द्र में रखकर आयोजित किया गया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि इस विषय को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए शिक्षित अर्थव्यवस्था के लिए भी हम सभी मिलकर वातावरण निर्माण बनाएं। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ महत्ती भूमिका निभा सकता है।

इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लेकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। आप सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद। जय हिन्द।